

# *NHRC urges youth to champion human rights and constitutional values*

**STATESMAN NEWS SERVICE**

*New Delhi, 4 October*

National Human Rights Commission (NHRC) Member Vijaya Bharathi Sayani called upon the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice, and contribute towards building a more inclusive and equitable society.

She made this appeal to students during the valedictory session of an online training programme aimed at sensitizing university students to the challenges of human rights in India.

In her address, Sayani urged the participants to become active defenders of human dignity and to use their knowledge for the greater good of society. She also encouraged



them to uphold constitutional principles in both their personal and professional lives.

On Friday, NHRC concluded its third Online Short Term Internship Programme (OSTI), which was attended by 74 students from 21 states and Union Territories across India. Inaugurated on 22 September by Bharat Lal, Secretary General

and CEO of NHRC, the programme included virtual tours of Tihar Jail, a police station, and the Asha Kiran Shelter Home in Delhi.

According to the Commission, these sessions offered young participants an opportunity to gain insights into the functioning of government institutions, the mechanisms

adopted to safeguard human rights, the realities faced on the ground, and the measures taken to protect vulnerable sections of society.

Sayani also commended NHRC's work as a guardian of justice and equality, highlighting its role in areas such as women's rights, child protection, mental health, custodial justice, and the empowerment of marginalized communities.

Through the OSTI programme, NHRC equipped students from diverse academic fields with practical tools to understand and address human rights issues. Interactive discussions and experiential learning exposed them to international law, human rights concerns in India, and effective advocacy strategies.

# सब कुछ कर रहा आईआईटी तो क्यों जा रही होनहारों की जान

सामाजिक कार्यकर्ता ने बीते साल एक माह में हुई तीन मौतों पर दाखिल की थी याचिका

संवाद न्यूज एजेंसी

कानपुर। पिछले साल एक माह में हुई तीन आईआईटी छात्र-छात्राओं की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर आईआईटी की ओर से 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें आत्महत्याएं रोकने के लिए कई प्रयास किए जाने की बात कही गई थी। छात्र धीरज सेनी के खुदकुशी के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आईआईटी सबकुछ कर रहा है तो फिर होनहारों की जान क्यों नहीं बच पा रही है।

एनएचआरसी में अगली सुनवाई पर



याचिकाकर्ता  
पंकज । संवाद

आईआईटी को इसका जवाब देना होगा।

पीएचडी छात्रा प्रियंका जायसवाल ने 18 जनवरी 2024 को आत्महत्या कर ली थी। इसके पहले 10 जनवरी को एमटेक छात्र विकास मीणा और 19 दिसंबर 2023 को शोध सहायक डॉ. पल्लवी चिल्का की मौत हो गई थी। 30 दिन में आईआईटी में तीन मौतों पर परेशान कल्याणपुर केशवपुरम निवासी सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार सिंह ने 20 जनवरी 2024 को एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें पिछले सालों में आईआईटी में हुई 15 आत्महत्याओं के कारणों की जांच कराने की मांग की थी। आईआईटी की ओर से एनएचआरसी को रिपोर्ट सौंपी गई थी। कहा गया था कि नौ परामर्शदाताओं की एक टीम 24 घंटे मौजूद रहती है जिनसे कॉल, ईमेल या हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क किया जा

धीरज का भी मुद्दा उठाएं

पंकज का कहना है कि कैपस के एक कमरे में एक छात्र का शव दो दिन फंदे पर झुलता रहता है और किसी कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगती। आत्महत्या को रोकने के माकूल प्रयास के टाले करने वाले आईआईटी प्रशासन को आत्महत्या की दो दिन तक जानकारी न मिलना बड़ा सवाल है। मामले की सुनवाई के दौरान धीरज के पक्ष को मजबूती से रखने की बात कही।

सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर कार्यशाला व सेमिनार होता है।

समेत अन्य कदम उठाने की बात कही गई थी। एनएचआरसी की ओर से यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता पंकज को भेजने के साथ आपत्ति मांगी गई थी। पंकज का कहना है कि आपत्ति भेज दी है। एनएचआरसी में अगली सुनवाई पर आईआईटी को जवाब देना होगा।

## **मानवाधिकार आयोग:आवेदन का मौका आज तक**

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी के एक पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए यूपी के आईपीएस अफसर रविवार तक आवेदन कर सकते हैं। आईजी कार्मिक शलभ माथुर के पत्र के मुताबिक आवेदन करने के लिए आईपीएस अफसरों को एसीआर ग्रेडिंग व संबंधित अन्य दस्तावेज 5 अक्टूबर तक जमा करना है। इसके बाद के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

NHRC.NIC

## **NHRC, India's Online Short Term Internship Programme- September 2025 concludes**

Press Release

National Human Rights Commission

<https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-india%E2%80%99s-online-short-term-internship-programme-september-2025-concludes>

New Delhi: 4th October, 2025

NHRC, India's Online Short Term Internship Programme- September 2025 concludes

74 University level students from 21 States and UTs successfully complete it

NHRC, India Member, Smt Vijaya Bharathi Sayani in her valedictory address urges youth to remain vigilant, raise their voices against injustice and help build a more inclusive and equitable society

The National Human Rights Commission (NHRC), India concluded its 3rd Online Short Term Internship Programme (OSTI) of 2025-2026 with 74 University level students from 21 States and UTs successfully completing it. The OSTI was inaugurated by Shri Bharat Lal, Secretary General on 22nd August, 2025.

Addressing the valedictory session as the Chief Guest, Smt Vijaya Bharathi Sayani, Member, NHRC congratulated the interns for successfully completing the enriching two-week journey and commended their dedication. Emphasising NHRC's role as a guardian of justice and equality, she highlighted the Commission's work in areas such as women's rights, child protection, mental health, custodial justice and the empowerment of marginalised communities.

Drawing attention to impactful sessions from experts in fields like psychology, forensic science and business and human rights, Smt Vijaya Bharathi Sayani praised the breadth of learning offered. Citing inspiring examples, she urged interns to become active defenders of human dignity, to use their knowledge for societal good and to uphold constitutional principles in both personal and professional spheres. She concluded with a call to action for the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice and help build a more inclusive and equitable society.

Smt Saidingpuui Chhakchhuak, Joint Secretary, NHRC, presented the internship report. Besides the sessions on different aspects of human rights by the NHRC Members and senior officers, experts and civil society representatives, the interns were also taken for virtual tours to the Tihar Jail, Police Station and Asha Kiran Shelter Home in Delhi. They were given an understanding of how different government institutions function, the mechanisms to protect human rights, the realities on the ground and the necessary steps

to protect the rights of vulnerable sections of society. Winners of the book review, group research project presentation and declamation competition were also announced.

Shri Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC, and Lt Col Virender Singh, Director, NHRC were present on the occasion.

The OSTI equips students from various academic fields with the tools to understand and address key human rights issues. Through hands-on learning and interactive discussions, participants explore international law, human rights concerns in India and practical advocacy methods.

\*\*\*\*\*

PIB

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

## **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का ऑनलाइन लघु अवधि इंटरनेट कार्यक्रम- सितंबर 2025 का समापन**

21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 74 विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने अपने समापन भाषण में युवाओं से सतर्क रहने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अधिक समावेशी एवं समतावादी समाज के निर्माण में योगदान का आग्रह किया।

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2174757>

Posted On: 04 OCT 2025 12:49PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 2025-2026 के अपने तीसरे ऑनलाइन लघु अवधि इंटरनेट कार्यक्रम (ओएसटीआई) का सफलतापूर्वक समापन किया, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 74 विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। इस ओएसटीआई का उद्घाटन महासचिव श्री भरत लाल ने 22 अगस्त, 2025 को किया था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षुओं को दो सप्ताह इस इंटरनेट कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने न्याय और समानता के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर जोर देते हुए, महिला अधिकार, बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, हिरासती न्याय और हाशिए पर रह रहे समुदायों के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया।

मनोविज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, व्यवसाय और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रभावशाली सत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्रीमती विजया भारती सयानी ने प्रदान की गई शिक्षा की सराहना की। उन्होंने प्रेरक उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रशिक्षुओं से मानवीय गरिमा के सक्रिय रक्षक बनने, अपने ज्ञान का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए करने और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक, दोनों क्षेत्रों में संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और एक अधिक समावेशी एवं समतामूलक समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैदिगपुई छकछुआक ने इंटरनेट रिपोर्ट प्रस्तुत की। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण आश्रय गृह का आभासी भ्रमण भी कराया गया। उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, मानव अधिकारों की रक्षा के तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी दी गई। इस दौरान पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की गई।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह उपस्थित थे।

ओएसटीआई विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के छात्रों को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। व्यावहारिक शिक्षण और संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय कानून, भारत में मानव अधिकारों की चिंताओं और व्यावहारिक तरीकों का अध्ययन करते हैं।

\*\*\*

पीके/केसी/जेके/एनके

(Release ID: 2174757) Visitor Counter : 47

PIB

## **NHRC ભારતનો ઓનલાઈન શોર્ટ-ટર્મ ઇન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ - સપ્ટેમ્બર 2025 પૂર્ણ થયો**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2174745>

21 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 74 યુનિવર્સિટી-સ્તરના વિદ્યાર્થીઓએ સફળતાપૂર્વક તે પૂર્ણ કર્યું

તેમના સમાપન સંબોધનમાં, NHRC, ભારતના સભ્ય શ્રીમતી વિજયા ભારતી સયાનીએ યુવાનોને સતર્ક રહેવા, અન્યાય સામે બોલવા અને વધુ સમાવિષ્ટ અને સમાન સમાજના નિર્માણમાં યોગદાન આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો.

Posted On: 04 OCT 2025 12:49PM by PIB Ahmedabad

રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ (NHRC), ભારતે 21 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 74 યુનિવર્સિટી-સ્તરના વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી સાથે 2025-2026 માટે તેનો ત્રીજો ઓનલાઈન શોર્ટ-ટર્મ ઇન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ (OSTI) સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો હતો. OSTIનું ઉદ્ઘાટન 22 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ સેક્રેટરી જનરલ શ્રી ભરત લાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

સમાપન સત્રને મુખ્ય અતિથિ તરીકે સંબોધતા, રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના સભ્ય શ્રીમતી વિજયા ભારતી સયાનીએ તાલીમાર્થીઓને બે અઠવાડિયાની સમૃદ્ધ યાત્રા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા બદલ અભિનંદન આપ્યા અને તેમના સમર્પણની પ્રશંસા કરી હતી. ન્યાય અને સમાનતાના રક્ષક તરીકે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગની ભૂમિકા પર ભાર મૂકતા, તેમણે મહિલા અધિકારો, બાળ સુરક્ષા, માનસિક સ્વાસ્થ્ય, કસ્ટોડિયલ ન્યાય અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયોના સશક્તિકરણ જેવા ક્ષેત્રોમાં આયોગના કાર્ય પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.

મનોવિજ્ઞાન, ફોરેન્સિક વિજ્ઞાન, વ્યવસાય અને માનવ અધિકાર જેવા ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતો દ્વારા યોજાયેલા શક્તિશાળી સત્રો તરફ ધ્યાન દોરતા શ્રીમતી વિજયા ભારતી સયાનીએ શિક્ષણની વ્યાપકતાની પ્રશંસા કરી હતી. પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણો ટાંકીને તેમણે તાલીમાર્થીઓને માનવ ગૌરવના સક્રિય રક્ષક બનવા, સામાજિક ભલા માટે તેમના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવા અને વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં બંધારણીય સિદ્ધાંતોને સમર્થન આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. તેમણે યુવાનોને સતર્ક રહેવા, અન્યાય સામે બોલવા અને વધુ સમાવિષ્ટ અને સમાન સમાજના નિર્માણમાં યોગદાન આપવા હાકલ કરી હતી.

રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના સંયુક્ત સચિવ શ્રીમતી સૈદિંગપુઈ છકછુઆકે ઇન્ટર્નશિપ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. માનવ અધિકાર આયોગના સભ્યો, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, નિષ્ણાતો અને નાગરિક સમાજના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા માનવ અધિકારોના વિવિધ પાસાઓ પરના સત્રો ઉપરાંત, ઇન્ટર્નને તિહાર જેલ, એક પોલીસ સ્ટેશન અને દિલ્હીમાં આશા કિરણ આશ્રય ગૃહનો વર્ચ્યુઅલ પ્રવાસ પણ કરાવવામાં આવ્યો હતો. તેમને વિવિધ સરકારી સંસ્થાઓની કામગીરી, માનવ અધિકારોના રક્ષણ માટેની પદ્ધતિઓ, જમીની વાસ્તવિકતાઓ અને સમાજના નબળા વર્ગોના અધિકારોના રક્ષણ માટે જરૂરી પગલાં વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. પુસ્તક સમીક્ષા, જૂથ સંશોધન પ્રોજેક્ટ પ્રસ્તુતિ અને ભાષણ સ્પર્ધાના વિજેતાઓની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના સંયુક્ત સચિવ શ્રી સમીર કુમાર અને રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના ડિરેક્ટર લેફ્ટનન્ટ કર્નલ વીરેન્દ્ર સિંહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

OSTI વિવિધ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોના વિદ્યાર્થીઓને માનવ અધિકારના મુખ્ય મુદ્દાઓને સમજવા અને સંબોધવા માટે જરૂરી સાધનો પૂરા પાડે છે. વ્યવહારુ શિક્ષણ અને ઇન્ટરેક્ટિવ ચર્ચાઓ દ્વારા, સહભાગીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા, ભારતમાં માનવ અધિકારોની ચિંતાઓ અને વ્યવહારુ હિમાયત પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરે છે.

SM/GP/NP/JT

સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : [@PIBAhmedabad](https://twitter.com/PIBAhmedabad) /pibahmedabad1964

(Release ID: 2174745) Visitor Counter : 20

The Statesman

### **NHRC urges youth to champion human rights and constitutional values**

She made this appeal to students during the valedictory session of an online training programme aimed at sensitizing university students to the challenges of human rights in India.

<https://www.thestatesman.com/india/nhrc-urges-youth-to-champion-human-rights-and-constitutional-values-1503494856.html>

Statesman News Service | New Delhi | October 4, 2025 5:15 pm

National Human Rights Commission (NHRC) Member Vijaya Bharathi Sayani called upon the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice, and contribute towards building a more inclusive and equitable society.

She made this appeal to students during the valedictory session of an online training programme aimed at sensitizing university students to the challenges of human rights in India.

In her address, Sayani urged the participants to become active defenders of human dignity and to use their knowledge for the greater good of society. She also encouraged them to uphold constitutional principles in both their personal and professional lives.

On Friday, NHRC concluded its third Online Short Term Internship Programme (OSTI), which was attended by 74 students from 21 states and Union Territories across India.

Inaugurated on 22 September by Bharat Lal, Secretary General and CEO of NHRC, the programme included virtual tours of Tihar Jail, a police station, and the Asha Kiran Shelter Home in Delhi.

According to the Commission, these sessions offered young participants an opportunity to gain insights into the functioning of government institutions, the mechanisms adopted to safeguard human rights, the realities faced on the ground, and the measures taken to protect vulnerable sections of society.

Sayani also commended NHRC's work as a guardian of justice and equality, highlighting its role in areas such as women's rights, child protection, mental health, custodial justice, and the empowerment of marginalized communities.

Through the OSTI programme, NHRC equipped students from diverse academic fields with practical tools to understand and address human rights issues. Interactive discussions and experiential learning exposed them to international law, human rights concerns in India, and effective advocacy strategies.

Pragativadi

## **NHRC Internship Empowers Youth to Champion Human Rights**

<https://pragativadi.com/nhrc-internship-empowers-youth-to-champion-human-rights/>

by Itishree Sethy | October 4, 2025 in National

Reading Time: 2 mins read

The National Human Rights Commission (NHRC), India wrapped up its third Online Short Term Internship Programme (OSTI) for 2025–2026.

The two-week program began on August 22 and ended in early October.

Seventy-four university students from 21 States and Union Territories participated. They engaged in sessions led by NHRC members, senior officers, experts, and civil society representatives.

Smt Vijaya Bharathi Sayani, NHRC Member, addressed the valedictory session. She praised the interns' dedication and encouraged them to raise their voices against injustice.

She emphasized NHRC's role in promoting justice, equality, and rights for women, children, and marginalized communities. She urged youth to uphold constitutional values and defend human dignity.

Interns attended expert-led sessions in psychology, forensic science, and business and human rights. They also took virtual tours of Tihar Jail, a police station, and Asha Kiran Shelter Home.

Smt Saidingpuui Chhakchhuak, Joint Secretary, NHRC, presented the internship report. She highlighted the program's impact and the students' active participation.

The NHRC announced winners of the book review, group research project, and declamation competitions. These activities encouraged critical thinking and advocacy skills.

Shri Samir Kumar and Lt Col Virender Singh also attended the closing ceremony. They applauded the interns' engagement and learning outcomes.

The OSTI aims to equip students with tools to address human rights issues. It blends academic insight with practical exposure to real-world challenges.

Impressive Times

## **NHRC Concludes 2025 Online Short Term Internship with 74 Students from Across India**

The National Human Rights Commission (NHRC), India successfully concluded its 3rd Online Short Term Internship Programme 2025-26, with 74 students from 21 States and UTs completing the training in human rights, advocacy, and constitutional awareness.

<https://impressivetimes.com/latest/nhrc-online-short-term-internship-2025/>

The Impressive Times | Sat, 04 October 2025

New Delhi– The National Human Rights Commission (NHRC), India successfully concluded its third Online Short Term Internship Programme (OSTI) for 2025-26, with 74 university-level students from 21 States and Union Territories completing the two-week programme. Inaugurated on 22nd August 2025 by Bharat Lal, Secretary General of NHRC, the internship offered students an opportunity to gain a comprehensive understanding of human rights issues and the workings of the Commission.

Vijaya Bharathi Sayani, Member of NHRC, addressed the valedictory session as the Chief Guest and congratulated the interns for their dedication throughout the programme. She highlighted the Commission's ongoing efforts in areas such as women's rights, child protection, custodial justice, mental health, and the empowerment of marginalized communities. She encouraged the students to use their learning to advocate for justice, defend human dignity, and uphold constitutional values in both personal and professional spheres.

During the internship, participants attended sessions conducted by experts in diverse fields including psychology, forensic science, and business and human rights. They also participated in virtual tours of institutions such as Tihar Jail, Delhi Police Stations, and Asha Kiran Shelter Home, which provided practical insights into government mechanisms for protecting human rights. The interns were introduced to the realities on the ground and the steps necessary to safeguard the rights of vulnerable populations. Awards were also announced for the book review, group research project presentation, and declamation competitions held during the programme.

Saidingpuii Chhakchhuak, Joint Secretary of NHRC, presented the internship report, while Samir Kumar, Joint Secretary, and Lt Col Virender Singh, Director, NHRC were also present during the valedictory session. The OSTI programme aimed to equip students from varied academic backgrounds with tools to understand, analyze, and address key human rights challenges, combining theoretical knowledge with hands-on learning and interactive discussions on both domestic and international human rights issues.

Punjab News Services

**Youth should lead fight against injustice: NHRC member Vijaya Bharathi Sayani**

<https://www.punjabnewsexpress.com/crime-justice/news/youth-should-lead-fight-against-injustice-nhrc-member-vijaya-bharathi-sayani-300323>

IANS | October 04, 2025 05:07 PM

NEW DELHI: National Human Rights Commission (NHRC) Member Vijaya Bharathi Sayani called upon the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice and help build a more inclusive and equitable society, an official said on Saturday.

Addressing the valedictory session of the 3rd Online Short-Term Internship Programme (OSTI) of 2025-2026 conducted by the Commission, Sayani urged the 74 interns to grow into active defenders of human dignity.

She asked the interns to use their knowledge for societal good and to uphold constitutional principles in both personal and professional spheres.

As many as 74 university-level students from 21 States and UTs completed the OSTI programme that was inaugurated by NHRC Secretary General Bharat Lal on August 22, said an official statement.

The OSTI equips students from various academic fields with the tools to understand and address key human rights issues. Through hands-on learning and interactive discussions, participants explore international law, human rights concerns in India and practical advocacy methods.

Sayani congratulated the interns for completing the enriching two-week journey and commended their dedication.

Emphasising NHRC's role as a guardian of justice and equality, she highlighted the Commission's work in areas such as women's rights, child protection, mental health, custodial justice and the empowerment of marginalised communities.

Drawing attention to impactful sessions from experts in fields like psychology, forensic science and business and human rights, Sayani praised the breadth of learning offered to the interns under the programme.

Citing inspiring examples, she urged interns to become active defenders of human dignity, to use their knowledge for societal good and to uphold constitutional principles in both personal and professional spheres.

She concluded with a call to action for the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice and help build a more inclusive and equitable society.

Lokmat Times

## Youth should lead fight against injustice: NHRC member Vijaya Bharathi Sayani

<https://www.lokmatimes.com/national/youth-should-lead-fight-against-injustice-nhrc-member-vijaya-bharathi-sayani/amp/>

By IANS | Updated: October 4, 2025 16:15 IST

New Delhi, Oct 4 National Human Rights Commission (NHRC) Member Vijaya Bharathi Sayani called upon the youth to ...

New Delhi, Oct 4 National Human Rights Commission (NHRC) Member Vijaya Bharathi Sayani called upon the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice and help build a more inclusive and equitable society, an official said on Saturday.

Addressing the valedictory session of the 3rd Online Short-Term Internship Programme (OSTI) of 2025-2026 conducted by the Commission, Sayani urged the 74 interns to grow into active defenders of human dignity.

She asked the interns to use their knowledge for societal good and to uphold constitutional principles in both personal and professional spheres.

As many as 74 university-level students from 21 States and UTs completed the OSTI programme that was inaugurated by NHRC Secretary General Bharat Lal on August 22, said an official statement.

The OSTI equips students from various academic fields with the tools to understand and address key human rights issues. Through hands-on learning and interactive discussions, participants explore international law, human rights concerns in India and practical advocacy methods.

Sayani congratulated the interns for completing the enriching two-week journey and commended their dedication.

Emphasising NHRC's role as a guardian of justice and equality, she highlighted the Commission's work in areas such as women's rights, child protection, mental health, custodial justice and the empowerment of marginalised communities.

Drawing attention to impactful sessions from experts in fields like psychology, forensic science and business and human rights, Sayani praised the breadth of learning offered to the interns under the programme.

Citing inspiring examples, she urged interns to become active defenders of human dignity, to use their knowledge for societal good and to uphold constitutional principles in both personal and professional spheres.

She concluded with a call to action for the youth to remain vigilant, raise their voices against injustice and help build a more inclusive and equitable society.

While presenting a report on the internship, NHRC Joint Secretary Saidingpuii Chhakchhuak, said that besides the sessions on different aspects of human rights by the NHRC Members and senior officers, experts and civil society representatives, the interns were also taken for virtual tours to the Tihar Jail, Police Station and Asha Kiran Shelter Home in Delhi.

They were given an understanding of how different government institutions function, the mechanisms to protect human rights, the realities on the ground and the necessary steps to protect the rights of vulnerable sections of society, she said.

--IANS

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

Organiser

**Andhra Christian pastors target women, children for conversion near Jagannath, Konark Temples to alter demography**

At the centre of the NHRC complaint are two key figures, Pastor Joshua Pattabhi and Tatipaka David alias T. David, accused of spearheading a covert Christian religious conversion network along Odisha's coast, particularly near Puri's Jagannath Temple and Konark Sun Temple with intent to alter the region's demography

<https://organiser.org/2025/10/04/319280/politics/andhra-christian-pastors-target-women-children-for-conversion-near-jagannath-konark-temples-to-alter-demography/>

Kunti Surender Oct 4, 2025, 09:00 pm IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Magistrate and the Superintendent of Police, Puri, on October 1, after taking cognisance of grave allegations of forced Christian conversions, unlawful burials and organised communal threats near Odisha's most revered Hindu pilgrimage sites the Jagannath Temple and the Konark Sun Temple. The action follows an emergency complaint filed by residents of Penthakata on 27 September 2025 alleging a "mass-scale plan to Christianise the Puri coast" under the guise of religious revival events; the NHRC has called for an Action Taken Report within two weeks and directed that all findings be shared with the Bench Secretariat for further examination.

**Pastors Under NHRC Lens: Pattabhi and David Named in Puri Conversion Plot**

At the centre of the NHRC complaint are two key figures, Pastor Joshua Pattabhi and Tatipaka David alias T. David, accused of spearheading a covert Christian religious conversion network along Odisha's coast, particularly near Puri's Jagannath Temple and Konark Sun Temple with intent to alter the region's demography.

The illegal Christian conversion event in Penthakata Puri was particularly targeting to convert poor Telugu & Odia Fisherman families especially women, minor children in the name of conducting "fasting revival".

**Pastor Joshua Pattabhi – The 'Night Conversion' Specialist**

Identified as the chief organiser of the conversion network, Pastor Joshua Pattabhi operates from Apostolic Fellowship Ministries in Rajahmundry, Andhra Pradesh. His online sermons and YouTube videos depict large-scale conversion gatherings across Chhattisgarh, Andhra Pradesh, and Odisha, often held late at night. Locals describe these as "night conversion drives", with Pattabhi openly asserting that "if a woman and children converts, the whole family follows."

According to complaints before the NHRC, his sessions reportedly combine psychological persuasion, monetary inducements, and the use of so-called 'magic remedies' or unknown substances that cause participants, particularly women and minors, to lose

consciousness, an act potentially breaching provisions of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954.

Residents further allege that Pattabhi's operations are sustained by foreign funding, with the pastor frequently travelling abroad to solicit support for his evangelical missions. In one widely circulated video, he boasted of converting 75 minor girls in Chhattisgarh during a night event, which locals condemned as "a blatant mockery of Indian law and culture."

In Puri, investigators say Pattabhi has sought to replicate his conversion model, organising discreet prayer meetings and "healing sessions" targeting women and children.

#### Tatipaka David alias T. David — The Local Enabler

T. David, who heads the Bethesda Revival Fellowship Church, Naringhapuram, is alleged to be Pattabhi's Odisha link. His videos under call for "revival" among coastal fishing communities. He reportedly handles logistics, mobilisation, and recruitment, targeting poor women, minors, and disabled persons with promises of money, medical help, and education.

Reportedly David's base at Christ Church, Penthakata, is cited as the hub of these activities, where he works alongside Pastor Mark to "alter the demography of Lord Jagannath's land."

#### Burials on the Beach

The complaint also accuses Pattabhi's followers of burying unknown bodies in coffins on Penthakata beach, allegedly to illegally claim land and convert the coastal stretch into a Christian cemetery. Locals provided geotagged videos showing the burials, suspecting a link to organ trafficking or criminal concealment in violation of forest and coastal protection laws.

#### Alleged Collusion and Negligence of Police Department

The complainants have also filed a follow-up petition on 2 October 2025 accusing Puri SP Prateek Singh and Sea Beach Police Station IIC Manas Chakra of wilfully allowing the conversion event to proceed despite prior warnings.

Speaking with Organiser, residents say they personally visited the SP's office, alerting him to the threat. However, instead of acting, the SP allegedly replied dismissively, saying "Haan thik hai..." and assured them that "police will only videotape prayers."

On 1 October, as the event began at 5 p.m., Pastor Pattabhi arrived and conducted "night conversions", live-streamed on YouTube via his channel "Apostolic Fellowship". The video reportedly showed minor girls, elderly women, and disabled women undergoing faith rituals. Within hours, the video was deleted, suggesting an attempt to destroy evidence a violation of Section 204 IPC (Destruction of Evidence).

The residents allege that the police were fully aware of the event's nature, yet chose to remain silent. They suspect "a nexus" between local police officers and the conversion organisers, claiming that undertakings were used as cover to legitimise illegal religious activity.

According to the complaint, nine illegal churches have been constructed in Penthakata with foreign funding, serving as "conversion command centres." These structures, locals allege,

double as hubs for drug trafficking, prostitution, and smuggling, posing a direct threat to coastal and national security.

The expansion of this missionary infrastructure, residents warn, forms part of a long-term plan to control India's eastern coastline, "from Kanyakumari to Puri," through religious conversion of coastal fishing communities — a demographic shift with strategic implications.

#### NHRC Action

Taking serious note of the allegations, the NHRC has directed the DM and SP of Puri to submit a detailed Action Taken Report and examine potential violations of:

Orissa Freedom of Religion Act, 1967

Juvenile Justice (Care & Protection) Act, 2015

Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954

The complainants have further sought disciplinary action through the DoPT against SP Prateek Singh and IIC Manas Chakra, and a central multi-agency probe involving MHA and NIA into the conversion nexus, foreign funding, and illegal burials.

Historically, Odisha has been a prime target of Christian evangelists for decades, with poor and innocent Vanavasi communities caught between Naxal and missionary forces. Swami Laxmananda Saraswati, who worked to strengthen local cultural roots, paid with his life for resisting this design. Though evangelisation is prohibited in designated tribal areas, these groups continue to defy the law, exploiting every opportunity to weaken indigenous traditions and faith. Their claims of "uplifting" locals mask a deeper agenda — one that insults the community, disconnects them from their roots, and revives the medieval zeal of evangelism, this time through the exploitation of women and children under the guise of faith and law.

New Indian Express

### **Nine villages in Raygada cry for a bridge: NHRC seeks report**

Patro alleged that the villagers are facing difficulties every day just to meet basic human needs.

<https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2025/Oct/04/nine-villages-in-raygada-cry-for-a-bridge-nhrc-seeks-report>

Express News Service | Updated on: 04 Oct 2025, 9:18 am

1 min read

**CUTTACK:** The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint highlighting the plight of nine remote villages in Raygada district that have remained cut-off from essential facilities due to the absence of a permanent bridge over the Nagabali river.

The complaint, filed by human rights activist and advocate Anup Kumar Patro of Jeypore, was admitted by the Commission on October 1, which has directed the Raygada collector to submit an action taken report within four weeks.

According to the complaint, the villages Tolosaja and Uppersaja (Sikaripai panchayat); Argonda, Mandipar and Kusabati (Palam panchayat) and Minajhola, Kuradi, Katapadu, and Raghunathpur (Majhiguda panchayat) under Kalyansinghpur block remain without a permanent bridge, severely hampering connectivity and access to basic facilities like healthcare, education, and clean drinking water.

The petitioner emphasised that these villages, even 76 years after independence, continue to face serious communication challenges due to the lack of proper infrastructure. The complaint alleged that this sustained neglect amounted to violation of fundamental rights guaranteed under Articles 14 and 21 of the Constitution of India.

Patro alleged that the villagers are facing difficulties every day just to meet basic human needs. The state and district administration have a constitutional obligation to ensure access to essential services, yet these communities remain deprived due to apathy.

The Commission after reviewing the matter forwarded the complaint to the district magistrate directing that appropriate action be taken and a report be submitted within four weeks.

Residents of these villages have reportedly made multiple appeals for a permanent bridge, but their voices have gone unheard.

Main Bhi Bharat

## 76 साल बाद भी नहीं बना पुल, NHRC ने मांगी रिपोर्ट

<https://mainbhibharat.co.in/adivasi-daily/bridge-still-not-built-after-76-years-nhrc-seeks-report/amp/>

MBB Desk

10 hours ago

ओडिशा के रायगढ़ ज़िले के दूरदराज़ के आदिवासी गाँवों की दशा एक बार फिर चर्चा में है।

नागावली नदी के किनारे बसे 9 आदिवासी गाँव आज भी बाकी दुनिया से कटे हुए हैं क्योंकि आज़ादी के 76 साल बाद भी वहाँ एक स्थायी पुल नहीं बन पाया है।

इस गंभीर उपेक्षा के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है और रायगढ़ जिला प्रशासन से चार हफ्ते के भीतर जवाब माँगा है।

यह मामला सिर्फ पुल का नहीं, बल्कि आदिवासी अधिकारों, विकास और प्रशासनिक उदासीनता की तस्वीर भी है।

इन गाँवों की कहानी दशकों पुरानी है। कल्याणसिंघपुर ब्लॉक की तीन पंचायतें – सिकारिपाई, पलाम और मझिगुड़ा – कई छोटे-छोटे गाँवों का घर हैं।

इनमें टोलोसाजा, अपरसाजा, अर्गोडा, मंडीपार, कुसाबटी, मिनाझोला, कुराडी, कटापाडु और रघुनाथपुर जैसे गाँव शामिल हैं।

इन सभी को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए नागावली नदी पर एक पुल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन अब तक यह सपना ही बना हुआ है।

इन गाँवों के लोगों की समस्याएँ केवल आने-जाने की नहीं हैं, बल्कि यह उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती हैं।

बारिश के मौसम में नदी में पानी का बहाव इतना तेज़ हो जाता है कि इसे पार करना नामुमकिन हो जाता है।

ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है।

इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए जयपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता अनुप कुमार पात्रो ने 17 जनवरी 2024 को NHRC में शिकायत दर्ज करवाई।

उन्होंने आरोप लगाया कि ज़िला और राज्य प्रशासन ने इन गाँवों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया है और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ भौगोलिक दूरी का नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत पर 1 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की और इसे गंभीर मानते हुए रायगढ़ जिला मजिस्ट्रेट से चार हफ्ते के अंदर Action Taken Report (ATR) मांगी है.

आयोग ने साफ कहा है कि यह एक मानवाधिकार का मामला है और सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए.

इस मामले की पृष्ठभूमि में यह जानना ज़रूरी है कि ओडिशा के कई आदिवासी क्षेत्र दशकों से इंफ्रास्ट्रक्चर यानि बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं.

पुल, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत चीजें अब भी कई गाँवों तक नहीं पहुँची हैं. बार-बार चुनावों में इन मुद्दों को उठाया जाता है, वादे किए जाते हैं लेकिन ज़मीन पर बदलाव नहीं दिखता.

इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी साफ नज़र आती है.

NHRC की कार्रवाई अब इस दिशा में उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है.

सवाल यह नहीं है कि पुल कब बनेगा, बल्कि सवाल यह है कि आदिवासी समुदाय को और कब तक अनदेखा किया जाएगा?

Madhyamam

### **Reflection of Muslim persecution in UP: Boy loses eyesight in police custody**

<https://madhyamamonline.com/india/reflection-of-muslim-persecution-in-up-boy-loses-eyesight-in-police-custody-1453636>

By Web Desk | POSTED ON: 4 OCT 2025 12:15 PM UPDATED ON: 4 OCT 2025

The case of a 13-year-old Muslim boy who was taken into custody and beaten in Muzaffarnagar, leading to the loss of vision in his left eye, reflects the UP Police's insensitive and divisive approach towards Muslims, as not even a minor boy was spared from being implicated in a false case, whereupon his father complained to the National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), and multiple district authorities.

Quoting the boy's father, The Indian Express reported that he was picked up by police after making an announcement in a local mosque about the reopening of the family's chicken shop, which had been closed for several days due to low demand during Navratri, while the announcement that chicken would be sold at reduced prices reportedly angered some residents who then complained to the police.

CCTV footage from the locality is said to show the minor being taken away in a police vehicle, and the family has claimed that this was the start of an ordeal that left the child with serious injuries and lasting damage to his vision.

The family reached the police outpost and saw the child confined behind bars with his feet tied, and they were initially told it was a minor matter and that the boy would be released later, but when they returned, they found him bruised and complaining of loss of sight.

The father was fined under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), and he alleged that this fine was imposed while the child was beaten inside custody, which created a situation where punishment was meted out without justification.

The police accused the family of possessing a country-made pistol after discovering an image on the boy's phone, and they claimed that the minor had confessed that the weapon belonged to his father, but the family argued that the picture was merely downloaded from the internet and that no such weapon ever existed.

The boy later stated that he had been beaten and videotaped until he repeated the version police wanted, and the father contended that this coerced statement was then used to falsely implicate him.

The family rushed the child to a community health centre where doctors noted diminished vision in one eye caused by trauma an hour earlier, and the boy was then referred to a hospital in Meerut for urgent surgery, while his condition remains under close medical observation.

A written complaint was filed with the NHRC, the NCPCR, the Muzaffarnagar Superintendent of Police, and the district child welfare committee, and the family alleged that their child was abducted, locked in an outpost, and brutally beaten, while they also claimed that threats of jail were issued to prevent them from pursuing action.

The police insisted that the boy had been suffering from a pre-existing eye condition for the past four years, and they suggested that the loss of vision could be linked to that history, while they also justified the fine imposed on the father as a measure to maintain peace in the area after the mosque announcement was deemed provocative.

The Hans India

### **Kerala woman dies of rabies, Human Rights Commission wants action plan**

<https://www.thehansindia.com/amp/news/national/kerala-woman-dies-of-rabies-human-rights-commission-wants-action-plan-1011844>

The Hans India | Update: 2025-10-04 15:00 IST

Pathanamthitta: A 65-year-old woman from Pathanamthitta died of rabies following a stray dog attack, prompting the Kerala State Human Rights Commission to direct the government to draw up an immediate action plan to prevent further deaths.

The victim, Krishnamma, a resident of Mannaramala, was bitten by a stray dog in the first week of September.

She had been undergoing treatment at Kottayam Medical College Hospital and had reportedly taken the anti-rabies vaccine.

During the attack, she fell to the ground and suffered a deep bite on her face.

Despite medical care, her condition worsened, and she succumbed to the infection.

The death comes amid an alarming surge in stray dog attacks across the state.

In the past five months alone, over 1.65 lakh people have been bitten by stray dogs, while 17 deaths have been reported due to rabies.

Taking note of the growing public health concern, Justice Alexander Thomas, Chairperson of the Kerala State Human Rights Commission, has instructed the government to prepare a comprehensive strategy to control rabies and manage the stray dog population.

The directive follows the recommendation of Jacob John, former head of Virology at the Christian Medical College (CMC), Vellore, who had called for the formation of a dedicated task force to coordinate rabies prevention measures across departments.

Justice Thomas also emphasised the importance of the Justice Siri Jagan Commission, constituted by the Supreme Court to fix compensation for dog bite victims, and asked the government to clarify whether the commission's work is still in progress.

The Additional Chief Secretary of the Local Self-Government Department has been asked to submit a detailed report within a month.

The Commission has initiated a suo motu case based on media reports, urging the state to adopt immediate steps to reduce stray dog attacks and prevent rabies-related deaths.

Indian Express

### **At 59, Punjab saw highest no. of clashes inside jails: NCRB data**

Data shows that in 2023, state released 2nd highest number of inmates on parole

<https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/punjab-highest-clashes-jails-ncrb-data-10286878/>

Written by Man Aman Singh Chhina

Chandigarh | Updated: October 4, 2025 10:35 AM IST

3 min read

Punjab saw the highest number of clashes (59) inside prisons in the country, as per the recently released National Crime Records Bureau (NCRB) data for the year 2023. The state was followed by Kerala (15) and Madhya Pradesh (14). Thus, Punjab jails have more than three times the clashes compared to their nearest competitor states in this parameter.

In other worrying prison statistics, data shows that the state releases second highest number of jail inmates on parole in the country and that it also has the third highest absconders from these paroles.

These statistics, coupled with many other important ones, points towards the need for urgent reforms in the prison system of the state especially in light of regular reports of the several major drug networks in the state being run from the prisons of Punjab.

During the year 2023, total of 25,483 people were released on parole in the country out of which the highest (6,577) were from Madhya Pradesh and the second highest were from Punjab (3,882). Gujarat followed at the third place with 2,969 people given parole.

When it comes to persons absconding on parole, Punjab again figures in the top three states. Gujarat has the maximum absconders at 109 followed by Madhya Pradesh (34) and Punjab (31).

For persons convicted for alcohol and drugs related offences in the country, Punjab is again at the top of the charts with the maximum 2,383 convictions in 2023 followed by Madhya Pradesh (1,201) and Bihar (931). Punjab's conviction rate for these specific offences are 25.6 per cent of the total convicted inmates lodged in the jails across the country for these cases.

As far as undertrials under prosecution for alcohol and drug related cases are concerned, Punjab cedes the top position to Bihar at 14,301, coming at second position with 9,073 undertrials followed by Uttar Pradesh at 5,063 persons. For undertrials in arms and explosives related offences too, Punjab is in the top three positions with Bihar at top with 2,840 persons, Uttar Pradesh (2,564) and Punjab with 1,223 persons.

Punjab is at the second position in the country when it comes to detention of undertrials for a period of one to two years with Uttar Pradesh topping the list at 10,283 persons, Punjab with 5,076 persons and Maharashtra with 4,978 persons.

For undertrials in special and local laws crimes taken cumulatively, Bihar has the maximum undertrials at 19,181 persons, Uttar Pradesh comes second at 11,010 persons and Punjab at third place with 10,832 persons.

Punjab also has the highest number of complaints which prisoners have submitted against their condition in prisons to the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commission (SHRC). The data shows that 345 complaints to various commissions were submitted from Punjab prisons in 2023 with the nearest highest number being 89 complaints from Uttar Pradesh and 68 complaints from Odisha.

Dainik Jagran English

## Telangana MLA T Raja calls for 'jihadi-free': Urges youth to protect religion & nation

<https://english.dainikjagranmpcg.com/politics/teelangana-mla-t-raja-calls-for-%E2%80%98jihadi-free%E2%80%99urges-youth-to-protect/article-5900>

Digital Desk | On 04 Oct 2025

In Indore, Telangana MLA T. Raja Singh called on citizens to make Madhya Pradesh free from "Love Jihad" and other threats. Speaking at the Ravan Dahan programme in the cantonment area on Vijayadashami, he administered an oath to the public to protect their families, religion, and country. He urged people to take inspiration from local traders and support policies for Hindu protection.

Raja said India's youth must remain vigilant. "Our young people must be ready to protect the nation, religion, and society. Those who act against these must be confronted," he said. He urged everyone to follow the path of Lord Ram and build a strong, disciplined society.

He claimed that today's 'Ravana' is a Love Jihadist who converts religion or promotes drug abuse. He warned that addicted youth cannot protect their families or country.

Raja addressed mothers and youth, saying, "If you must get addicted, be addicted to your country, your religion, or opposing Love Jihad. Addiction to drugs destroys lives and weakens society." He stated that youth wasting time on social media or drugs cannot fulfil their duty to the nation.

He highlighted areas in Indore, especially Azad Nagar, where Love Jihad incidents reportedly occur. Raja accused certain individuals of trapping Hindu girls by pretending to be Hindu, then converting them to Islam. He demanded authorities catch not just minor offenders but those providing financial and political backing.

He referenced a recent incident in Bhopal where around 500 Hindu boys were allegedly targeted in 27 madrasas. Raja thanked the **National Human Rights Commission** for investigating forced religious conversions.

Raja criticised some BJP MLAs, claiming they fear speaking out against Love Jihad for votes. He stated that demographic changes show a rising Muslim population and a declining Hindu population. "Hindus have the 'Hum Do Hamare Do' scheme, but jihadis have 'Hum Do Hamare 50'. If this continues, Hindu traditions could be restricted," he warned.

Raja applauded traders in Sitlamata Market, Indore, for putting up "Jihadi-Free Market" banners. He urged all citizens to replicate this across Madhya Pradesh. He warned that Love Jihad begins with small actions, like noting phone numbers at shops, and grows into larger schemes.

Using a mobile torch, Raja administered an oath to the attendees:

- ☐ Protect family, religion, and country.
- ☐ Make Madhya Pradesh free from Love Jihad.
- ☐ Ensure Hindu sisters are safe from conversion attempts.
- ☐ Buy only from Hindu-owned businesses, whether it costs Rs 1 or Rs 1 lakh.

He urged citizens to uphold these pledges as a lifelong commitment.

#### Role of RSS and Hindu values

Raja praised the RSS for teaching both life and sacrifice. He said RSS prepares youth to protect the country, like Chhatrapati Shivaji, and mothers to act as warriors like Ahilya Bai. He spoke about RSS relief work during natural disasters, helping people regardless of religion.

He stressed that Hindu youth must learn courage and commitment, while women should inspire the next generation with strength and wisdom.

Dainik Bhaskar

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य कौशांबी आएंगे:8 अक्टूबर को मानवाधिकारों की करेंगे समीक्षा

<https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/kaushambi/news/national-human-rights-commission-member-will-come-to-kaushambi-136089013.html>

पंकज केसरवानी | कौशांबी 4 घंटे पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो 8 अक्टूबर 2025 को कौशांबी जिले का दौरा करेंगे। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने उनके प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों की समीक्षा के लिए उदयन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सदस्य कानूनगो मानवाधिकारों और समावेशी विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। इनमें रोजगार एवं कौशल विकास का अधिकार, बच्चों के अधिकार, किशोर न्याय प्रणाली, मानव तस्करी, वृद्धजनों के अधिकार और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं।

इसके अलावा, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासी निकायों के कामकाज, खेल और मानवाधिकार, युवा मामले, सांस्कृतिक, दार्शनिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में मानवाधिकारों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। बाल यौन शोषण सामग्री के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सदस्य किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.), बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.), जेल विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर) और अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित अधिकारों की भी समीक्षा करेंगे। समीक्षा से पहले, वे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनपद के नागरिकों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समय पर सभी तैयारियां पूरी करने को कहा।

Dainik Bhaskar

**कलेक्टर और आबकारी आयुक्त NHRC के समन पर नहीं पहुंचे:कांग्रेस ने पारदर्शी जांच की मांग की, रहवासियों ने आयोग को दी आपत्ति**

<https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/the-collector-and-the-excise-commissioner-failed-to-respond-to-the-nhrc-summons-136090067.html>

भोपाल 47 मिनट पहले

राजधानी की अरेरा कॉलोनी में चल रही सोम ग्रुप की शराब दुकान के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में चल रही सुनवाई के तहत भोपाल कलेक्टर और आबकारी आयुक्त को आयोग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था। आयोग ने दोनों अधिकारियों को 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन में जिला प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन आयोग के समक्ष अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच प्रतिवेदन में रहवासियों के पक्ष को शामिल नहीं किया गया।

कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि रहवासियों की बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अरेरा कॉलोनी के आवासीय क्षेत्र में संचालित यह दुकान आर्य समाज मंदिर और अनुश्री नर्सिंग होम के पास स्थित है, जिसके कारण रहवासी असुविधा महसूस कर रहे हैं।

त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 28 जुलाई 2025 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से 15 दिनों में कार्रवाई प्रतिवेदन मांगा था। आयोग द्वारा 19 अगस्त को स्मरण पत्र भेजे जाने के बाद भी प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद समन जारी किया गया।

रहवासी लवनीश भाटी, सुनीता शर्मा, डॉ. अनुश्री गुप्ता और आचार्य शास्त्री ने भी आयोग को भेजे गए पत्र में बताया कि जांच के दौरान उनसे कोई बयान नहीं लिया गया। रहवासियों ने इस दुकान को बंद करने की मांग की है।

विवेक त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस ने मांग की है कि इस शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाए और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।

Dainik Bhaskar

**अरेरा कॉलोनी में शराब दुकान की फिर से शिकायत:मानवाधिकार आयोग ने दिया था नोटिस, जवाब देने पेश नहीं हुए आयुक्त-कलेक्टर**

<https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/complaint-again-about-liquor-shop-in-arera-colony-136092593.html>

भोपाल 3 घंटे पहले

अरेरा कॉलोनी के आवासीय प्लॉट पर चल रही शराब दुकान को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को 15 दिनों में कार्रवाई प्रतिवेदन पेश न करने का नोटिस दिया था। बावजूद इसके, अब तक प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है। इसके साथ आबकारी आयुक्त को भी समन जारी किया गया था।

शिकायतकर्ता विवेक त्रिपाठी और लवनिश भाटी ने रहवासियों की ओर से लिखित शिकायत भेजकर शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें कहा गया है कि आवासीय मकान में शराब दुकान चलाई जा रही है। मालूम हो कि पिछले दिनों एडीएम की टीम ने शराब दुकान से अस्पताल और मंदिर की नपती की थी, जिसमें 42 मीटर पर मंदिर मिला था। इधर, आबकारी अफसरों का तर्क है कि आर्य समाज का मंदिर शासन के न्यास में दर्ज नहीं है, जिससे इसे शामिल नहीं किया गया है।

होटल कर्व में ड्राई डे पर परोसी शराब -2 अक्टूबर को ड्राई डे के दिन बैरागढ़ स्थित होटल कर्व में शराब पार्टी आयोजन का वीडियो वायरल हुआ है। होटल में आने वाले लोगों को शराब परोसने का बिल भी तारीख के साथ दिया गया है। ऐसे में आबकारी अमले की सक्रियता पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं।

दो तस्करों से 8 पेटी शराब जब्त

शहर के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में एक युवक द्वारा घर से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही आबकारी टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया ने बताया कि शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टीबी अस्पताल के पास बाजपेयी नगर ईदगाह हिल्स में आशीष बड़गुजर और विशाल कनाड़े शराब तस्करी कर रहे हैं।

इसके बाद उनसे 8 पेटी शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत तीस हजार रुपए आंकी गई है। टीम यह भी पता लगा रही है कि तस्कर शराब कहां से ला रहा था।

Hindustan

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी के लिए आवेदन मांगे

Lucknow News - लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी के एक पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए यूपी के

<https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/lucknow/story-up-ips-officers-can-apply-for-dig-post-at-nhrc-by-sunday-201759589329587.html>

Newsrap हिन्दुस्तान, लखनऊ Sat, 4 Oct 2025 08:18 PM

लखनऊ, विशेष संवाददाता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी के एक पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए यूपी के आईपीएस अफसर रविवार तक आवेदन कर सकते हैं। आईजी कार्मिक शलभ माथुर के पत्र के मुताबिक आवेदन करने के लिए आईपीएस अफसरों को एसीआर ग्रेडिंग व संबंधित अन्य दस्तावेज 5 अक्टूबर तक जमा करना है। इसके बाद के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।